बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 183 ● नई दिल्ली ● बुधवार 06 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नाले में गिरकर दो साल की बच्ची की मौत का मामला, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के जेई की नौकरी खत्म

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलस्वा डेयरी स्थित मुकुंदपुर इलाके के एक खुले नाले में गिरने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) ने अनुबंध पर रखे जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से बच्चों की, जो सबसे अधिक मासूम होते हैं।

बंगाल विजय का जश्न, सीएम रेखा गुप्ता ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन संग काली मंदिर में टेका मत्था

नई दिल्ली । देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा का कमल खिल चुका है। भाजपा ने टीएमसी को पटखनी देते हुए 206 सीटें हासिल की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सीआर पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मां काली के चरणों में शीश नवाने के बाद मुख्यमंत्री ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक भगवा शान से लहरा रहा है। यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में इस बिल का विरोध किया था, बंगाल की माताओं-बहनों ने उन्हें अपने वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब दिया है। बंगाल की महिलाओं ने भय, आतंक और तुष्टिकरण की राजनीति को नकारकर यह सिद्ध कर दिया है कि नारी शक्ति अब अपने सम्मान और अधिकारों के लिए किसी भी दमनकारी शक्ति से टकराने

को तैयार है। उन्होंने कहा कि बंगाल में यह जीत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण की नीति की जीत है। भय, आतंक और अत्याचार के वातावरण के बावजूद बंगाल की महिलाओं ने निर्भीक होकर मतदान किया और लोकतंत्र को सशक्त बनाते हुए सुशासन की सरकार स्थापित की। आज की यह जीत उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने बंगाल की मिट्टी को अपने पसीने और रक्त से सींचा है। यह जीत लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास की जीत है। भय के वातावरण के बावजूद बंगाल की जनता ने लोकतंत्र को सशक्त बनाते हुए सुशासन की सरकार चुनने का जो साहस दिखाया है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा है। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत अभिनंदन, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को प्रधानमंत्री मोदी अपने नेतृत्व में आगे ले जा सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि सभी राज्यों में शांति और समृद्धि रहे। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज और ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय भी उपस्थित थीं। बता दें कि बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली भाजपा ने अनथक संघर्ष के जरिये तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। तृणमूल महज 80 सीटों पर सिमट गई, जो पिछले चुनाव में भाजपा की 77 सीटों से सिर्फ तीन अधिक है। भाजपा की ओर से सीएम पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के साथ भवानीपुर सीट पर कांटे के मुकाबले में ममता खुद हार गईं। उनके 20 मंत्री भी हार गए।

महिला आरक्षण पर आर-पार के मूड में कांग्रेस, अलका लांबा ने छेड़ा हक का राष्ट्रव्यापी अभियान

नई दिल्ली ।

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने 5 मई को शिमला से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के पारित होने के बावजूद महिला आरक्षण कानून को लागू करने में विफल रहने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लांबा ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर कानून लागू करने में देरी करके देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण कानून पारित हो चुका है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। फिर भी भाजपा सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? लांबा ने आरोप लगाया कि भाजपा ऐतिहासिक रूप से महिला आरक्षण का विरोध करती रही है और उन्होंने इस कानून को पारित कराने में कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की मंशा होती, तो महिलाओं को 2014 में ही उनके अधिकार मिल जाते। विपक्ष के दबाव में ही सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई। हमने इसे पारित करवाना सुनिश्चित किया। उन्होंने परिसीमन या जनगणना प्रक्रियाओं से जोड़े बिना कानून को तत्काल लागू करने की मांग की और जोर देते हुए कहा कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर यह कानून आज लागू होता है, तो लगभग 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। भाजपा महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रही है? लांबा ने आरक्षण ढांचे में ओबीसी महिलाओं को शामिल किए जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कानून को तुरंत लागू करें और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित करें। भाजपा न तो कानून लागू करने को तैयार है और न ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शामिल करने को। इन मांगों को मनवाने के लिए लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक विशाल पोस्टकार्ड अभियान की घोषणा की, जिसमें देशभर की दस लाख महिलाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि यह तो जन आंदोलन की शुरुआत मात्र है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गांवों, विधानसभा क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हम हर पंचायत, हर वार्ड, हर जिले तक पहुंचेंगे। महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगी और अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगी।

200 करोड़ की ठगी मामला- अभिनेत्री लीना मारिया को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री लीना मारिया को एक बड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। यह मामला 200 करोड़ रुपये के धन शोधन से संबंधित है। हालांकि, मकोका मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

लीना मारिया अपने पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ इन मामलों में आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में उनकी भूमिका और सबूतों पर विचार किया। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह फैसला अभिनेत्री के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। मकोका मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में उन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर भी कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इन दोनों पर कई वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप हैं। जांच एजेंसियां इन मामलों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। अदालत ने दोनों मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखा। पिछली सुनवाई के दौरान लीना की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि उनके और सुकेश चंद्रशेखर के संबंध अब सामान्य नहीं हैं और दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि सुकेश का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है। जब अदालत ने इस महिला की पहचान के बारे में पूछा, तो लीना की ओर से पेश वकील ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम लिया था, जिससे मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया था। गौरतलब है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में लीना मारिया को सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर द्वारा कथित रूप से किए गए 200 करोड़ रुपए के ठगी में लीना की भूमिका की भी जांच की। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और यह मामला पहले से ही काफी चर्चा में रहा है। यह मामला साल 2021 में उस वक्त सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बाद में, पता चला कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से सामने आया। जानकारी के मुताबिक, जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी।

मोदी लहर में नहीं जीती, तो अब कैसे? अरविंद्र केजरीवाल ने बीजेपी की जीत पर उठाए बड़े सवाल

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की जीत पर सवाल उठाए हैं। यह जीत पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वह लंबे समय से इस राज्य में हाशिए पर रही है, जहां वर्षों से कांग्रेस, वामपंथी दलों और बाद में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि भाजपा ने बंगाल में कैसे प्रवेश किया, और इस बात पर जोर दिया कि यह ऐसे समय में हुआ जब मोदी की लोकप्रियता राज्यों में गिर रही थी। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली और बंगाल, जहां भाजपा मोदी लहर के चरम पर भी जीत हासिल नहीं कर सकी... 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में, उन्हें सिर्फ 3-3 सीटें मिलीं। उसी दिल्ली और बंगाल में भाजपा ने तब जीत हासिल की जब पूरे देश में मोदीजी की लोकप्रियता बिल्कुल निचले स्तर पर गिर रही थी... कैसे? वहीं, एक रैली में केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण और गला घोंटा है। पिछले तीन-चार महीनों से हम बंगाल में अराजकता को अपनी आँखों से देख रहे हैं। उन्होंने बिहार और महाराष्ट्र में भी यही किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरी विधानसभा में, मेरे जेल जाने से पहले, 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौटा, तो केवल 1,06,000 वोट बचे थे। उन्होंने छह महीनों के भीतर 42,000 वोट कम कर दिए। पिछली बार मैं 30,000 वोटों से जीता था। 42,000 वोट रद्द कर दिए गए। मैं 3,000 वोटों से हार गया। आप कैसे जीत सकते हैं? जब आप सारे वोट रद्द कर देंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही अराजकता पूरे देश में चल रही है। आज लोकतंत्र संकट में है। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के लिए रवाना हो गया है ताकि आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के हाल ही में भाजपा में ÷विलय÷ का मुद्दा उठाया जा सके, जिनमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल जैसे नेता शामिल हैं।

मोदी और शाह की चुनावी रणनीति गजब की होती है, इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है: शशि थरूर

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति और संगठन क्षमता की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं ने पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में प्रभावी प्रदर्शन किया है, जो उनकी मजबूत संगठन शक्ति और चुनाव संचालन की दक्षता को दर्शाता है। थरूर ने कहा कि इन दोनों नेताओं की कार्यशैली पेशेवर है और वह चुनाव अभियान में संसाधनों का व्यापक उपयोग करते हैं। थरूर ने यह भी स्वीकार किया कि अन्य दलों विशेषकर कांग्रेस, को इस प्रकार की रणनीति और संगठन से सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता में आने के बाद इन नेताओं का संदेश देश को जोड़ने वाला होगा, न कि विभाजन करने वाला। इसके साथ ही थरूर ने कांग्रेस की स्थिति पर भी स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने केरल में कांग्रेस की जीत की सराहना करते हुए कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि पार्टी सही रणनीति अपनाए तो अन्य राज्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस को अब गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले भी इस आवश्यकता को स्वीकार कर चुकी है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे व्यवहार में उतारा जाए। थरूर ने कहा कि केरल में जो रणनीति सफल रही, उसका विश्लेषण कर उसे अन्य राज्यों में लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए।

उपजते रोग

ऐसी बीमारियां जो अस्वस्थ आदतों की वजह से होती हैं और इन्हें सही जीवनशैली से रोका जा सकता है, उन्हें जीवनशैली विकार कहते हैं। इस तरह की बीमारियों में डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग और कैंसर तक शामिल हैं। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ ही लोगों की उम्र पर निर्भरता बढ़ रही है और शारीरिक गतिविधियां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। इसके अलावा प्रिज़र्वेटिव बेस्ड जंक और प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता चलन, धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन शहरों से लेकर गांवों तक तेजी से बढ़ रहा है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, गलत खानपान और तनाव मिलकर इन बीमारियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की रिपोर्ट राष्ट्रीय चिंता बढ़ाने वाली है कि देश की पचास फीसदी आबादी जीवनशैली से जुड़े रोगों से ग्रस्त-त्रस्त है। यह भी चिंता बढ़ाने वाला है कि एक दशक पहले देश में खान-पान, जीवन व्यवहार व तनाव से उपजे रोगों का प्रतिशत जहां 31 था, जो अब पचास फीसदी तक जा पहुंचा है। कहीं एक अच्छी बात यह है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार व नये शोध अनुसंधान के चलते संक्रामक रोगों का प्रतिशत घटा है लेकिन हमारे खानपान व जीवन व्यवहार में तेजी से आ रहे बदलावों के चलते लोग मोटापे, मधुमेह, तनाव व उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते जानलेवा संकट भी बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार साल 2021 में गैर संक्रामी रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 43 मिलियन से ज्यादा है। इनमें से 82 फीसदी मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें हृदय से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। 2021 में यह आंकड़ा 19 मिलियन था। इसके बाद कैंसर, सांस संबंधी बीमारियों और डायबिटीज का नंबर आता है। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जीवनशैली से संबंधित बीमारियां दुनियाभर में खासतौर पर भारत जैसे देशों में कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद देश में आम आदमी के जीवन स्तर में किसी न किसी तरह सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके चलते जीवनशैली भी बदली है लेकिन पौष्टिक व शरीर की जरूरतों के अनुकूल भोजन न करने, शारीरिक निष्क्रियता, स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की कमी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इन रोगों के वाहक बनते हैं। इसमें आनुवंशिक रोगों की भी भूमिका है। धीरे-धीरे शरीर को खोखला करने वाले ये रोग कालांतर जानलेवा बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी चिंता जता रहे हैं कि भारत में विभिन्न रोगों से मरने वाले यादातर लोगों की मौत की वजह संक्रामक रोग के बजाय जीवनशैली से जुड़े रोग हैं। जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान की आशातीत प्रगति के चलते आम भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है लेकिन जीवनशैली से जुड़े रोगों का बढ़ना इस कामयाबी पर पानी फेरने जैसा है। यही वजह है कि देश में स्वास्थ्य बीमा कारोबार में तेजी आई है, यह तेजी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। लेकिन ये बीमा कंपनियां रोग से बचाव में मदद करने के बजाय व्यक्ति के रोगों के इलाज को प्राथमिकता देती हैं। देर रात तक मोबाइल व इंटरनेट पर सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से हमारी नींद में खलल पड़ रहा है। नींद पूरी न होने से तनाव व अवसाद बढ़ रहा है। हमारा देर से भोजन करना, देर से सोना और सुबह देर से उठना भी रोगों का कारक बना है। हमने जबसे खाने में पारंपरिक पौष्टिकता के बजाय स्वाद को प्राथमिकता देनी शुरू की है, तभी से शरीर में जरूरी विटामिनों की कमी बढ़ी है। प्रदूषित खान-पान की भी इस संकट में भूमिका है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट हल्की शारीरिक गतिविधियां वाली एक्सरसाइज या 75 मिनट तक इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे न सिर्फ वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि यह हृदय रोग, तनाव और डायबिटीज जैसे दूसरे जीवनशैली विकारों से भी बचाव करता है। किसी एक सदस्य की बीमारी केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है बस बल्कि उससे पूरा परिवार, समाज और देश प्रभावित होता है। जब व्यक्ति बीमारियों की वजह से अपनी दिनचर्या खुद नहीं संभाल पाता तो परिवार के दूसरे सदस्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

इससे न सिर्फ बीमार व्यक्ति बल्कि घर के दूसरे सदस्यों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। भारत जैसे मध्य और निम्न आय वर्ग वाले देशों में इलाज का बोझ परिवार का बजट खराब कर देता है और बहुत बार तो पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। यह बीमारियां कामकाजी लोगों की प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालती हैं। इसके अलावा बीमार की असामयिक मौत परिवार के लिए जीवन भर का ट्रॉमा भी बन जाती है। हालांकि देश में जीवनशैली से जुड़े रोगों से बचाव के लिये जागरूकता जरूर आई है। जिसके लिये एनडीए सरकार को श्रेय देना होगा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग का दुनिया में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। यह जागरूकता भारत में भी है। लेकिन बड़ी आबादी अब भी इससे दूर है। प्रधानमंत्री 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम व अन्य मंचों से मोटापे से बचाव और खानपान में मिलेट अपनाने पर अक्सर बल देते नजर आते हैं। लेकिन इस पर सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित अनुपात में नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि लोगों को महंगा इलाज कराने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसी बीमारियां जिन्हें हम मेहनतमंद आदतों और खान-पान अपना कर रोक सकते हैं उनके रोकथाम के लिए कोशिश करना बेहद जरूरी है। बीमारी शुरू होने से पहले अगर उसे रोका जा सके, तो यह इलाज करवाने से बेहतर होता है। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां धीरे-धीरे शरीर को खोखला करती हैं लेकिन सजग रहकर और स्वस्थ आदतों को अपनाकर इनसे न केवल बचा जा सकता है बल्कि एक खुशहाल जीवन भी जिया जा सकता है।

बंगाल में कमल का खिलना !

देश के चार रायों तमिलनाडु केरल, असम व प. बंगाल के साथ एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र पुडुचेरी में गत माह सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है उससे केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है, मगर दूसरी ओर उसने कांग्रेस पार्टी को भी निराश नहीं किया है। एक तरफ असम, बंगाल व पुडुचेरी में जनता ने भाजपा व उसके गठबन्धन एनडीए को गद्दी सौंपी है तो दूसरी तरफ केरल में उसने कांग्रेस के गठबन्धन को सत्ता के आसन पर बैठा दिया है। मगर भाजपा को दोहरी सफलता मिली है। प. बंगाल में इस पार्टी ने धुआंधार धमाकेदार जीत दर्ज करके पिछले 15 वर्षों से शासन कर रही क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। इन चुनावों में प. बंगाल के चुनावों पर पूरे देश की नजर थी क्योंकि यहां भाजपा की तृणमूल कांग्रेस से सीधी टक्कर थी और भाजपा के पास कोई कद्दावर क्षेत्रीय नेता भी नहीं था। यह एक कड़वा सच है कि स्व. प्रोफेसर हरिपद भारती के बाद जनसंघ या भाजपा का राय में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं हुआ है जिसके नेतृत्व को आगे रख कर पार्टी चुनावी मैदान में उतरती। अतः पार्टी ने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जिसकी रणनीति स्वयं गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने बनाई। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि श्री मोदी की लोकप्रियता में राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है। रायों के ये चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पश्चिम एशिया युद्ध के साये में हुए जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। विपक्षी नेताओं ने इस युद्ध को लेकर श्री मोदी व उनकी सरकार की कड़ी आलोचना भी की मगर देश की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध के कुप्रभावों से भारत को बचाने में मोदी सरकार ने जो रणनीति बनाई और पैट्रोल-डीजल व ईंधन गैस के दामों को जिस प्रकार थामे रखा, उसका असर यह पड़ा कि लोगों में सरकार की छवि बरकरार रही और इसका लाभ उसे चुनावों में भी मिला। इसके साथ ही इन रायों में जहां-जहां भी भाजपा मौजूद थी वहां उसके पक्ष में हवा चली। असम व पुडुचेरी में पहले से ही भाजपा-एनडीए सरकारें थीं। इन रायों में सत्ता विरोधी लहर नहीं चल पाई और भाजपा को विजयश्री मिली। साथ ही बंगाल में जहां भाजपा विपक्ष में थी वहां इसे सत्ता कब्जाने में सफलता प्राप्त की। इसका प्रमुख कारण भी श्री मोदी की लोकप्रियता ही मानी जा रही है। मगर इसके पीछे हिन्दू-राष्ट्रवाद का सिद्धान्त भी काम कर रहा है जो कि भाजपा की मुख्य विचारधारा है। प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता दी सरकार को हराना लोहे के चने चबाने जैसा था मगर यहां भी मोदी मैजिक काम आया, क्योंकि राय में प्रधानमन्त्री ने घोषणा कर दी थी कि राय के सभी भाजपा प्रत्याशियों को दिया गया वोट उन्हें ही दिया गया वोट समझा जायेगा। हालांकि इस राय में भाजपा को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अपने चुनाव प्रचार को बहुत धारदार बनाना पड़ा। राय में ममता दी की पार्टी ने भाजपाई नेताओं को बाहरी बता कर जो प्रचार किया उसे जनता ने पसन्द नहीं किया और प्रखर राष्ट्रवाद के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। ऐसा पहली बार हुआ कि यह राय जनसंघ या भाजपा की झोली में गया। इससे इस पार्टी के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी पूरा हुआ। बंगाल के भाजपा की झोली में आने के बाद अब गंगोत्री (उत्तराखंड) से लेकर गंगासागर (बंगाल) तक के रायों में भाजपा का शासन ही हो गया है। जहां तक केरल में कांग्रेस की जीत का सवाल है तो इस राय में भाजपा का कोई खास वजूद नहीं है मगर कांग्रेस ने यहां मार्क्सवादी पार्टी के गठबन्धन को पराजित करके सिद्ध कर दिया कि भारत जैसे धर्म प्राण देश में कम्युनिस्ट सिद्धान्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। केरल के अलावा साम्यवादियों का प्रभाव 2011 तक बंगाल में था। मगर इस वर्ष हुए राय चुनावों में ममता दी ने वामपंथियों को ठिकाने लगा दिया था। दरअसल बंगाल में शानदार जीत दर्ज करके भाजपा ने सभी राजनैतिक पंडितों को चौंकाया है क्योंकि इन चुनावों में चुनाव आयोग ही स्वयं एक मुद्दा बना हुआ था और ममता दी लगातार उसकी आलोचना इसलिए कर रही थीं कि इसने 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से सघन पुनरीक्षण के नाम पर काट दिये थे। इनमें से 27 लाख ऐसे थे जिन्होंने 2002 में या तो वोट डाला था अथवा उनका वंशावलि सम्बद्ध था। (चुनाव आयोग की मतदाता सूची में बने रहने की यह एक शर्त थी)।

इसके बावजूद राय में 93 प्रतिशत रिकार्ड मतदान हुआ था मगर फिर भी ममता दी के हाथ पराजय ही लगी। पुडुचेरी में एनडीए की पहले भी सरकार थी। लोगों ने इसी सरकार को दोहराने का मन बनाया। इसी प्रकार असम में भी श्री हेमन्त बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा नीत सरकार को दोहराया गया। लेकिन दक्षिण के सबसे प्रमुख राय तमिलनाडु में इस बार फिल्म अभिनेता विजय की नई पार्टी ने जिस तरह बाजी मारी है और सत्तारूढ़ द्रमुक की स्टालिन सरकार को सत्ता से उतारा है वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। राय में फिल्मी हस्तियों में नेतृत्व ढूंढने की अपनी अलग राजनैतिक परंपरा रही है। यहां द्रमुक सरकार के मन्त्रियों ने जिस प्रकार हिन्दू संस्कृति को अपना निशाना बनाया था उसका दुष्प्रभाव भी मतदाताओं पर पड़ा। कुल मिलाकर ये चुनाव भारत में लोकतन्त्र को

सम्पादकीय...

प्रदेश में उन्नत तकनीक के साथ औद्यानिक क्रांति से शाहजहांपुर में समृद्ध होते किसान

उत्तर प्रदेश सरकार राय के किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की कृषि व्यवस्था में विविधता लाने और पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का समावेश करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राय का उद्यान विभाग इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश का किसान अपनी मेहनत और उन्नत कृषि विधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। औद्यानिक फसलों, जैसे फल, सब्जी, और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का व्यापक प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है और किसान परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के कुशल निर्देशन में अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (डफ्ब्) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं किसानों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला रही हैं। जनपद शाहजहांपुर में इस मिशन के अंतर्गत किए गए प्रयास एक मिसाल बनकर उभरे हैं। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप, प्रशासन ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी क्रम में शाहजहांपुर के ग्राम गंगसरा पुवायां के एक प्रगतिशील किसान श्री गोविन्द सिंह की सफलता की गाथा उल्लेखनीय है। पूर्व में पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने के कारण उन्हें बढ़ती लागत और घटती आय जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश सरकार की औद्यानिक विकास की योजनाओं और एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में अपनी खेती की दिशा बदली। उन्होंने पारंपरिक फसलों के स्थान पर 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद की बागवानी शुरू की। सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान और तकनीकी सहायता ने उनके इस निर्णय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अमरूद की उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया। इस परियोजना में प्रति हेक्टेयर लगभग 1.50 लाख रुपये की लागत आई, जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता ने किसान का मनोबल बढ़ाया। जब फसल तैयार हुई, तो विपणन की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के तंत्र ने सहयोग किया। उद्यान विभाग और मण्डी समितियों के समन्वय से फसल को सीधे प्रक्षेत्र से ही व्यापारियों द्वारा क्रय कर लिया गया, जिससे किसान को बिचौलियों से मुक्ति मिली और उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ। श्री गोविन्द सिंह को समस्त खर्चे निकालने के बाद लगभग 2.00 से 2.25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। उनकी यह उपलब्धि

महिला आरक्षण पर भाजपा सरकारों का तमाशा जारी

महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर भाजपा का तमाशा जारी है। आरक्षण के लिए पहले से पारित नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाने, उस पर भाषण देने और राष्ट्रीय चैनल पर देश को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अब बारी भाजपा की राय सरकारों की है। भाजपा की राय सरकारें विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर उसमें परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रस्ताव मंजूर कर रही है और सत्र में कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों की आलोचना कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया और 27 अप्रैल को सत्र में नारी शक्ति वंदन कानून के समर्थन में एक सरकारी प्रस्ताव मंजूर किया गया। परिसीमन करने और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का समर्थन किया गया। प्रस्ताव पारित किए जाने के समय कांग्रेस ने वाकआउट किया। इसी तरह 28 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का सत्र आहूत किया गया। इसमें भी महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ और विपक्ष की आलोचना की गई। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह विपक्षी पार्टियों का कहना था कि सरकार अभी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव ले आए वे उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने कहा कि सरकार आज प्रस्ताव ले आए कि लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें हैं, उनमें से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही तो विपक्ष उसका तुरंत समर्थन करेगा, लेकिन भाजपा को तो तत्काल महिला आरक्षण करना नहीं है, उस पर तमाशा करना है।

पुराने मामलों में चुनाव के समय छापेमारी

अब तो पांच रायों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई रुक जाएगी। जिन रायों में चुनाव हो गए वहां छोड़ कर अब एजेंसियां उन रायों का रुख करेंगी, जहां जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। असल में पिछले दिनों केंद्रीय एजेंसियों खास कर ईडी ने चुनावी रायों में जम कर छापेमारी की।

वह छापेमारी भी ऐसे मामलों में हुई, जो कई बरस पुराने हैं और जिन मामलों में मे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और आरोपी जेल काट कर निकल भी चुके है। पश्चिम बंगाल में 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई और उसके 12 दिन बाद जब पहले चरण के नामांकन का काम पूरा हो रहा था। तब से लेकर 19 अप्रैल तक यानी पहले चरण का प्रचार बंद होने से दो दिन पहले तक ईडी ने आठ अलग-अलग मामलों में 50 जगह छापे मारे। ये सारे छापे 2020 में दर्ज एफआईआर से जुड़े मामलों में मारे गए।

पश्चिम बंगाल अपवाद नहीं है। केरल में जनवरी के महीने में 21 जगहों पर छापे मारे गए और वह मामला भी 2025 के गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है। इसी तरह तमिलनाडु में 2025 के टैस्मैक घोटाले से जुड़े मामले में 2026 में चुनाव से ठीक पहले छापेमारी हुई। केरल और तमिलनाडु के दोनों मामलों में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। अब पंजाब में भी छापेमारी की शुरुआत हो गई। अगले साल मार्च मे वहां चुनाव होने वाले है।

बंगाल के 34 लाख मतदाताओं का क्या होगा

पश्चिम बंगाल के 34 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में है। इनमें से 27 लाख आठ हजार से कुछ यादा लोग तो ऐसे हैं, जिनके पास जरूरी कागजात है। इनको तार्किक विसंगति के आधार पर मतदाता सूची से बाहर किया गया है। इनके मामले सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 न्यायाधिकरण बनाए हैं, जिसमें कछुआ चाल से सुनवाई हो रही है। इन 19 न्यायाधिकरणों ने पहले चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल से दो दिन पहले तक 657 मामलों की सुनवाई की थी। इनमें से 139 लोगों को नाम की मंजूरी दी गई। मतदान के दूसरे चरण से पहले 1,468 और लोगों के नाम की मंजूरी दिए जाने की खबर आई। अब सवाल है कि बाकी बचे हुए लोगों का क्या होगा?

जिस रफ्तार से न्यायाधिकरण काम कर रहे है उससे तो सारे मामले सुनने मे कई महीने लगेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ समय का नहीं है। यह भी है कि न्यायाधिकरण से जिन करीब 80 फीसदी लोगों के नाम खारिज होंगे, उनका क्या होगा?

गौरतलब है कि न्यायाधिकरण के सामने तार्किक विसंगति वाले 27 लाख नामों के अलावा सात लाख और आपत्तियां आई हैं। अगर इनमें से 20 फीसदी यानी सात लाख के नाम क्लीयर होते हैं तो बाकी का क्या होगा? क्या उन सबको विदेशी मान कर देश से निकाला जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति मतदाता होने के योग्य नहीं है क्या वह देश में रहने के योग्य है? क्या उसका आधार कार्ड या राशन कार्ड बन सकता है और वह नागरिक सुविधाओं का लाभ ले सकता है?

राघव चड्ढा को भाजपा का पहला सबक

आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा चार्टर्ड एकाउंटेंट की पढ़ाई करने के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम किया था। वहां उन्हें यह लिबर्टी थी कि बाकी नेताओं की तरह वे भी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह सके। मीडिया में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी राघव चड्ढा या दूसरे नेता अरविंद कहते थे। बहुत सम्मान देना हुआ तो अरविंद जी कह दिया। हालांकि यह भी कम ही होता था। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं चलता है। असल में भाजपा ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले तो उन्होंने बातचीत में उनको नितिन नवीन जी कह कर संबोधित किया। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राघव चड्ढा से कहा कि नाम लेने की बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह कर संबोधित करें। यह भाजपा का कल्चर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा नितिन नवीन को लेकर कुछ यादा ही संवेदनशील हो गई है। उसे लग रहा है कि अगर प्रयास करके नहीं दिलाया गया तो लोग नितिन नवीन को वह सम्मान नहीं देंगे, जो उनसे पहले अन्य अध्यक्षों को मिलता रहा है। इसीलिए सवाल है कि ऐसा अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी, जिसे सम्मान दिलाने के लिए इतना प्रयास करना पड़े?

ब्रिक्स बैठक में भारत अलग-थलग पड़ा

दिल्ली में ब्रिक्स के उप विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई। कमाल की बात है कि हर अंतरराष्ट्रीय बैठक को अभूतपूर्व बता कर उसका प्रचार करने वाली केंद्र की मोदी सरकार इस पर बिल्कुल मौन रही। ब्रिक्स प्लस की बैठक में कौन-कौन आया और क्या हुआ इस बारे में लगभग खामोशी रही। बैठक 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी। इसकी चर्चा तब शुरू हुई, जब बैठक के बाद साझा बयान जारी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स के देशों ने इजराइल की भूमिका की सख्त आलोचना की थी, जिसे वे साझा बयान में शामिल करना चाहते थे। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस वजह से आम सहमति नहीं बनी और ब्रिक्स की ओर से साझा बयान जारी नहीं हुआ। गौरतलब है कि भारत के पास अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता है। इसीलिए ईरान चाहता था कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते भारत इजराइल और अमेरिका के हमले की निंदा करे। लेकिन भारत ने दोनों देशों के हमले की निंदा नहीं की। ब्रिक्स प्लस की बैठक में भारत ने साझा बयान से इजरायल की आलोचना हटा कर या कुछ नरमी लाकर उसे मंजूर कराने का प्रयास किया, लेकिन रूस, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सबने इसका विरोध किया। सोचने वाली बात है कि ब्रिक्स प्लस के 10 देशों में से नौ ने भारत के प्रयास का साथ नहीं दिया, जबकि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है।

योगी सरकार की पहल से युवाओं को मिले अंतर्राष्ट्रीय अवसर

उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अब इसे वैश्विक स्तर तक विस्तार देने की ठोस रणनीति अपनाई गई है। सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को अब न केवल देश के भीतर, बल्कि विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। सेवायोजन निदेशालय के माध्यम से संचालित 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है, जिसने राय के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया अब व्यवस्थित और संस्थागत रूप ले चुकी है। इस कार्य के लिए मिशन द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से आधिकारिक रिक्रूटिंग एजेंसी का लाइसेंस प्राप्त किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशों में रोजगार की प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से संचालित हो। प्रदेश के हजारों युवाओं को इजराइल जैसे देशों में निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग 9000 निर्माण श्रमिकों का चयन किया गया, जिनमें से 6004 श्रमिक विदेशों में जा चुके हैं। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होगी। जो राय की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगें।

इसके अतिरिक्त, 1336 श्रमिकों को इजराइल भेजने की प्रक्रिया जारी है और फरवरी 2026 में भी 245 श्रमिकों का चयन किया गया है। इन श्रमिकों को आवश्यक औपचारिकताओं जैसे पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद विदेश भेजा जाएगा। रोजगार मिशन की पहल केवल निर्माण क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वर्तमान में 5000 केयरगिवर्स को इजराइल और जापान में तथा 1000 नर्सों को जर्मनी में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल से उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के कुशल, अर्द्धकुशल एवं तकनीकी कामगारों को दुबई और ओमान जैसे देशों में लगभग 2000 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया है। यह विविधता इस बात का संकेत है कि प्रदेश के युवाओं की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए रोजगार मेलों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

सेवायोजन निदेशालय द्वारा आयोजित इन मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2026 तक 13,698 रोजगार मेलों और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 17,26,163 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इन रोजगार मेलों ने युवाओं और नियोक्ताओं के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य किया है। रोजगार के साथ-साथ सही मार्गदर्शन भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2026 तक 29,172 काउंसलिंग कार्यक्रमों में 33,11,737 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के विभिन्न विकल्पों की जानकारी दी गई, जिससे वे अपने कैरियर को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। रोजगार मिशन के तहत 'इंडस्ट्री कनेक्ट' कार्यक्रमों का आयोजन कर उद्योगों और युवाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।

22 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों, शिक्षण संस्थानों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस तरह के कार्यक्रमों से उद्योगों की आवश्यकताओं और युवाओं के कौशल के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्किल गैप को कम करने में मदद मिलती है। प्रदेश में आयोजित रोजगार महाकुंभ कार्यक्रमों ने भी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त 2025 में लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में 16,212 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 1612 युवाओं को यू0ए0ई और ओमान जैसे देशों में रोजगार के अवसर मिले है। इसी प्रकार गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल प्लेसमेंट ड्राइव और वाराणसी में आयोजित काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में भी हजारों युवाओं का चयन हुआ। प्रदेश में रोजगार के अवसरों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में आयोजित इंटरनेशनल मोबिलिटी कॉनक्लेव में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, रिक्रूटिंग एजेंसियों और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मंच पर सुरक्षित और नैतिक प्रवासन (म्जीपबंस डपहतंजपवद) पर विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत किया गया। इस प्रकार के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार मिले। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए 'पिंक रोजगार महाकुंभ' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2765 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 79 महिलाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिले। यह पहल दर्शाती है कि योगी सरकार महिलाओं को भी वैश्विक रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुंबई और पुणे में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों और रिक्रूटिंग एजेंसियों से संवाद स्थापित किया गया। टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स और अन्य संस्थानों के साथ बैठकें कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशिक्षण संस्थानों के मॉडल का अध्ययन कर उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार की परिकल्पना अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक स्तर तक विस्तारित हो चुकी है। योगी सरकार के नेतृत्व में रोजगार मिशन ने युवाओं को नई दिशा और नए अवसर प्रदान किए हैं।

विदेशों में रोजगार, रोजगार मेले, करियर काउंसलिंग और उद्योगों से सीधा संवाद सभी उद्यम मिलकर एक मजबूत रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। इसी गति से इस प्रयास से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न केवल देश के भीतर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कुशल मानव संसाधन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। यह पहल न केवल युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि राय की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशील एस्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/00862)

डेढ़ लाख शिक्षामित्र परिवारों को संभाला हमारी सरकार ने- मुख्यमंत्री

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें ने बिना नियम-कानून के शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो पूरी तरह नियम-विरुद्ध था। उनकी इस गलती के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। ऐसे में हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। डेढ़ लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत पर आ सकते थे। ये लोग 18-19 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में वे कहां जाते? तब हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि इनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इनका सहयोग लेंगे। 2017 में ही सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। अब इसे और बढ़ते हुए 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जो अप्रैल महीने से लागू भी हो गया है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षामित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समारोह में शिक्षामित्रों का किया सम्मान

पिछली सरकारों ने बिना नियम-कानून के सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो पूरी तरह नियम-विरुद्ध था-मुख्यमंत्री

ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता हमारा नेचर, सकारात्मक भाव से ही तैयार कर सकते हैं अच्छी पीढ़ी- सीएम योगी

सीएम बोले- शिक्षक या शिक्षामित्र नकारात्मक सोच रखेंगे, तो बच्चों की नींव कमजोर करेंगे और इससे समाज व राष्ट्र की क्षति होगी

संवाद और सहयोग से किया समय का समाधान

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अब ट्रेड यूनियन वाली सोच और नकारात्मक वृत्ति को पूरी तरह त्याग देना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक या शिक्षामित्र केवल मांगों पर अड़े रहेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो न केवल बच्चों की नींव कमजोर करेंगे बल्कि पूरे समाज व राष्ट्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता। पहले देश, फिर हम। सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले ही अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। सरकार सकारात्मक सोच के साथ आपके साथ है, इसलिए नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वर्षों से चली आ रही आपकी मांग को सरकार ने संवाद व सहयोग के माध्यम से हल किया, न कि टकराव के रास्ते से।

सभी शिक्षामित्रों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में एक शिक्षामित्र परिवार आया था, जिसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, डायलिसिस की जरूरत है। इसीलिए मैंने शिक्षामित्रों को भी प्रधानमंत्री की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा देने का निर्णय किया था। 5 लाख रुपये का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर सभी शिक्षामित्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो छूट गए होंगे, उन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही एक भव्य समारोह आयोजित कर सभी को यह कार्ड प्रदान किया जाएगा।

बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल सभी शिक्षामित्रों के बैंक खाते खुलवाने का निर्देश दिया गया है। इससे मानदेय सीधा एकाउंट में आएगा। सरकार ने शिक्षामित्रों को उनके जिले व नजदीकी विद्यालय में तैनाती देने की व्यवस्था की है। खासकर विवाहित महिला शिक्षामित्रों को मायके या ससुराल के निकट विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया है और यह परिवर्तन साफ दिख रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की हालत बदली गई है। पहले जहां टॉयलेट, पेयजल, फ्लोरिंग, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास की उपलब्धता मात्र 30-36फीसदी थी, वह अब 96-99फीसदी हो गई है। ड्रॉपआउट दर 19फीसदी से घटकर 3फीसदी पर आ गई है।

मत करें चिंता, हर समस्या का कराएंगे समाधान- मुख्यमंत्री

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करिए, सरकार हर समस्या का प्रभावी समाधान कराएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाते हुए पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लिए तथा समीप खड़े अफसरों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध और निष्पक्ष होना चाहिए। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कहा यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्चस्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनीं सीएम योगी ने

जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं अधिकारी, कराएं पारदर्शी निस्तारण- मुख्यमंत्री

गोशाला में गोवंश को दुलारकर खिलाया गुड़

गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। मंगलवार सुबह वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गोशाला में मुख्यमंत्री ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

सीएम योगी ने दी अंबरीश श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिविल लाइंस पार्क रोड निवासी, प्रतिष्ठित कारोबारी एवं वरिष्ठ समाजसेवी अजय कुमार श्रीवास्तव (अतुल) के आवास पर जाकर उनके दिवंगत पुत्र अंबरीश श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अंबरीश श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के मंत्री थे। 24 अप्रैल को उनका असामयिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबरीश श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत की आत्मा की चिर शांति के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने अंबरीश के पिता अजय कुमार श्रीवास्तव (अतुल), माता संध्या श्रीवास्तव, पत्नी दीपाली श्रीवास्तव, अनुज नितिन श्रीवास्तव, अंबरीश के पुत्रों ईशान श्रीवास्तव व वीर श्रीवास्तव और अन्य परिजनों आदित्य श्रीवास्तव, पारूल श्रीवास्तव, तनुजा श्रीवास्तव, विराज श्रीवास्तव, अनन्या श्रीवास्तव, नव्या श्रीवास्तव, अमित कुमार श्रीवास्तव, गोरख प्रसाद, डॉ. अंकुर सिन्हा आदि से आत्मीयता से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल व अन्य कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गोरखपुर में शिक्षामित्र सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण, कुशीनगर में प्रमाण पत्र वितरित

कुशीनगर। गोरखपुर में आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार, कुशीनगर में किया गया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बढ़े हुए मानदेय के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षामित्रों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम में प्रदेश की राय मंत्री ग्राम्य विकास, समग्र विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार नवाचार कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आधुनिक तकनीक, एआई एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 1999 में लागू शिक्षामित्र योजना के तहत वर्तमान में लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं। पूर्व में ?3500 प्रतिमाह मानदेय को बढ़ाकर अगस्त 2017 में 10,000 किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। यह वृद्धि 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी है तथा इसके लिए 230.11 करोड़ की धनराशि जनपदों को जारी की जा चुकी है। साथ ही शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ड्रॉपआउट दर 15 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई है, जबकि ट्रांजिशन दर 78 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं 36 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत तक पहुंच चुकी हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हजारों विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब एवं डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 6 से 12 तक उन्नत करने, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं तथा डीबीटी के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक सामग्री हेतु धनराशि हस्तांतरण जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। स्कूल चलो अभियान÷ के अंतर्गत इस सत्र में लगभग 20 लाख नए नामांकन भी दर्ज किए गए हैं। अंत में मंत्री ने शिक्षामित्रों से आह्वान किया कि वे समर्पण भाव से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान जनपद के विभिन्न विकासखंडों के चयनित शिक्षामित्रों को प्रतीकात्मक रूप से बढ़े हुए मानदेय के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक रामकोला विनय कुमार गोंड सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

गविष्टि धर्मयुद्ध : सरकार को शंकराचार्य की दो टूक— गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, वरना खड़ी होगी चतुरंगिनी सेना

देवरिया।

उत्तराम्नाय योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गविष्टि (गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध) यात्रा के तीसरे दिन देवरिया के वैकुंठपुर की धरती वैचारिक क्रांति की गवाह बनी। श्री राम मंदिर प्रांगण में आयोजित विद्वत गोष्ठी को संबोधित करते हुए जगद्गुरु ने वर्तमान व्यवस्था और तथाकथित हिंदू सरकारों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारें सबसे बड़ा अधर्म कर रही हैं, क्योंकि आज भारत बीफ एक्सपोर्ट (गो-मांस निर्यात) में विश्व में शीर्ष पर है। शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया और उन्हें पशु की श्रेणी से बाहर नहीं निकाला, तो आगामी 24 जुलाई को लखनऊ की सड़कों पर 2,18,700 सैनिकों वाली चतुरंगिनी सेना के साथ निर्णायक शंखनाद होगा।

वैकुंठपुर में जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राजनीति और व्यवस्था पर बोला तीखा हमला; बीफ एक्सपोर्ट में भारत के शीर्ष पर होने को बताया शर्मनाक; 24 जुलाई को लखनऊ में 2,18,700 सैनिकों की अक्षौहिणी सेना के साथ शक्ति प्रदर्शन का एलान।

विदेशी विचारधारा की दासता और सनातनी राजनीति का अभाव

जगद्गुरु ने देश के प्रमुख राजनैतिक दलों—भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा—को एक साथ आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत की मूल सनातनी विचारधारा आज नेतृत्व विहीन है। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ भाजपा अमेरिकी पूंजीवाद की राह पर है, वहीं कांग्रेस ब्रिटिश परंपरा की पोषक है; जबकि समाजवादी और साम्यवादी क्रमशः रूस और चीन की विचारधारा से प्रभावित हैं। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि राम, कृष्ण और विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा वाली शुद्ध भारतीय राजनीति आखिर कहाँ है? उन्होंने आह्वान किया कि देश की 70 करोड़ सनातनी जनता को अब 30 करोड़ के पीछे चलने की विवशता त्यागनी होगी और वेद-शास्त्रों को प्रमाण मानने वाली स्वतंत्र राजनैतिक धारा को प्रोत्साहन देना होगा।

महाराष्ट्र का उदाहरण और संवैधानिक गरिमा का प्रश्न

संबोधन के दौरान महाराजश्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी दो प्रमुख मांगें पुनः दोहराईं— गाय को राय माता का दर्जा देना और उसे सरकारी दस्तावेजों में मवेशी या कैटल जैसे अपमानजनक शब्दों से मुक्त कर पृथक सम्मानित सूची में स्थान देना।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके आग्रह पर यह साहसिक निर्णय ले सकते हैं और कोई कानून आड़े नहीं आता, तो उत्तर प्रदेश में यह इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिख रही? उन्होंने स्पष्ट किया कि सन्यासी स्वयं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वह समाज को ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो।

जन-जन का संकल्प और 24 जुलाई की डेडलाइन

मंगलवार को यात्रा मुंडेरा बाबू, बंजरिया, कंचनपुर, सोनुघाट और शिवबनकटा जैसे क्षेत्रों से गुजरी, जहाँ जन-जन ने गविष्टि के संकल्प के साथ गौ रक्षा की शपथ ली। गोष्ठी के समापन पर ऋग्वेद के मंत्रों के साथ सामूहिक शपथ दिलाई गई कि गौ माता को सताने वाली आसुरी शक्तियों को पराजित किया जाएगा। शंकराचार्य ने सभी श्रद्धालुओं से 1008.guru पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की और घोषणा की कि यदि 81 दिनों की इस यात्रा के अंत तक सरकार नहीं जागी, तो लखनऊ में महाभारत कालीन एक अक्षौहिणी सेना का जमावड़ा होगा। यह घोषणा न केवल धार्मिक है, बल्कि सत्ता के गलियारों में एक बड़े राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल की आहट मानी जा रही है।

मास्टर पॉलिसी के बिना करोड़ों के फ्लैट असुरक्षित, सुरक्षा का सामूहिक कवच भी गायब, करे कोई, भरे कोई

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर की ऊंची इमारतों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक कड़वा सच ये है कि उनका सपनों का आशियाना एक अदृश्य वित्तीय खतरे के साये में खड़ा है। हाईराइज सोसाइटियों में रहने का ढांचा तो सामूहिक है, सुरक्षा और आर्थिक भरपाई का तंत्र मौजूदा समय पूरी तरह व्यक्तिगत स्तर पर सिमटा है। विशेषज्ञ बता रहे कि भारत में मास्टर स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस की अनिवार्यता न होने और इसे ठीक तरीके से लागू न होना एक ऐसा कानूनी और वित्तीय गैप है, जो किसी भी बड़े हादसे के बाद सैकड़ों परिवारों की जीवनभर की कमाई को मलबे में बदल सकता है। हाईराइज की हकीकत ये है कि यहां निजी लापरवाही जैसी कोई चीज नहीं होती। आग चाहे ग्राउंड फ्लोर के मीटर रूम में लगे या 25वीं मंजिल के किचन में इमारत का पूरा स्ट्रक्चर एक ही धमनियों से जुड़ा है। अगर बीच की मंजिल का कंक्रीट चटकता है, तो ऊपर भी नुकसान होता है।

हाईराइज सोसाइटी में करे कोई, भरे कोई

हाईराइज सोसाइटी में हर फ्लैट एक दूसरे से कंक्रीट और स्टील से जुड़ा होता है। अगर पहली या इससे ऊपर की मंजिल के किसी एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो उसका प्रभाव केवल उस घर तक सीमित नहीं रहता।

धुएं से ऊपर की मंजिलें काली होती हैं, तो दमकल की बौछारों से नीचे की मंजिलों में भारी सीपेज होता है। सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब आग से बिल्डिंग का मुख्य ढांचा कमजोर हो जाए। ऐसी स्थिति में, यदि पूरी बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है, तो सजा उन परिवारों को भी भुगतनी पड़ती है जिनकी कोई गलती नहीं थी। सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, यानी अगर आपकी कार से किसी और का नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। लेकिन करोड़ों की कीमत वाले फ्लैट्स के मामले में ऐसा कोई अनिवार्य कानून नहीं है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने कहा कि यदि पड़ोसी की लापरवाही से घर जल जाता है या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर असुरक्षित हो जाता है, तो वर्तमान व्यवस्था में सीधे तौर पर पड़ोसी से मुआवजा मिलने की कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है। नीचे के फ्लैट में लगी आग ऊपर फैलती है और ऊपर वाले फ्लैट मालिक के पास अपना बीमा है, तो उसकी कंपनी उसे क्लेम देगी। दूसरा, उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जहां से आग शुरू हुई, तो उसकी बीमा कंपनी अन्य प्रभावित फ्लैटों को भुगतान करेगी। यदि बीमा नहीं है और आग किसी की लापरवाही से लगी है, तो पीड़ित पक्ष लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत दोषी पर केस करेगा।- अंकित मान, एडवोकेट।

इंदिरापुरम का हाल क्लिक विहार में हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में आबादी के बढ़ने के मुकाबले फायर विभाग के पास उपकरण, स्काई लिफ्टर, सीढ़ी, जाल व जनशक्ति की कमी है। इमारतों में फायर एनओसी 5 साल के लिए वैध है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है।

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर ईसी सख्त

मुख्य सचिव-डीजीपी को दिया निर्देश, किसी भी सूरत में शांति हो बहाल

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हिंसा की खबरों पर चुनाव आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मंगलवार को राज्य प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है।

हिंसा की घटनाओं पर आयोग की कार्रवाई

चुनाव आयोग ने यह सख्त निर्देश राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हुई हिंसक वारदातों के बाद जारी किए हैं। मंगलवार को बंगाल में हिंसा की अलग-अलग घटनाओं में कथित तौर पर दो लोगों की जान चली गई। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों से राजनीतिक दलों के कार्यालयों में तोड़फोड़ और लूटपाट की खबरें भी सामने आई हैं। इन घटनाओं की गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने आला अधिकारियों को तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लेने को कहा है।

शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट की कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव बाद की हिंसा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहा है। इसमें शामिल व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

प्रशासन और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल पर जोर

आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। अधिकारी ने आगे कहा, स्थिति को काबू में रखने के लिए पर्याप्त तैनाती और प्रशासन-सीएपीएफ के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों के राज्यपालों को अधिसूचना जारी कर नई विधानसभा का रास्ता साफ कर दिया।

ममता का इस्तीफा देने से इनकार

शुभेंदु अधिकारी ने दी नसीहत, कहा- संविधान में सब लिखा है

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद भी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार करते हुए पद से इस्तीफा न देने का मन बनाया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वे न तो हारी हैं और न ही इस्तीफा देंगी।

संविधान का हवाला देकर शुभेंदु ने घेरा

ममता बनर्जी के इस अड़ियल रुख पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है। शुभेंदु ने इस पूरे विवाद पर बहुत नपी-तुली और संविधानिक टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, सब कुछ संविधान में लिखा है। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का यह इशारा साफ है कि लोकतंत्र में हार-जीत और पद पर बने रहने की प्रक्रिया संविधान के नियमों से चलती है। बंगाल की हाई-प्रोफाइल चुनावी जंग के बाद अब सारा मामला कानूनी और संविधानिक मर्यादाओं के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है। ममता बनर्जी के बयान को उनके समर्थकों ने उनके जुझारू व्यक्तित्व से जोड़ा है, वहीं भाजपा इसे नियम विरुद्ध बता रही है।

ममता बनर्जी ने क्या कहा था?

पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सूबे में पार्टी की हार के बाद भड़क गई हैं। मंगलवार को मीडिया ने उनसे लोकभवन जाकर इस्तीफा देने के बारे में सवाल पूछा। इस पर दीदी ने कहा, मैं क्यों जाऊंगी? हम तो हारे नहीं हैं, जो जाएंगे। अगर मैं जीत गई होती तो शपथ से पहले इस्तीफा देने जाती। लोकभवन जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चोरी करके जीतने से उन्हें अगर लगता है कि मुझे इस्तीफा देना होगा तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कहती हूं कि हम हारे नहीं हैं। उन्होंने जबरन हमें हराया है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो जीते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर मेरी जीत हुई है।इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की संभावना को पूरी तरह से नकारते हुए एक अनोखा तर्क पेश किया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू थी, जिसके दौरान सरकार का संचालन मुख्यमंत्री के बजाय मुख्य सचिव के हाथों में था। बनर्जी के अनुसार, जब ममता बनर्जी पिछले तीन महीनों से तकनीकी रूप से प्रशासनिक कामकाज नहीं संभाल रही थीं, तो उनके इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने विपक्षी दलों की मांग को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अपने पद पर बनी रहेंगी। कल्याण बनर्जी ने चुनाव परिणामों की शुचिता पर भी कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है। टीएमसी सांसद ने दावा किया कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने उनके उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंटों के साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें केंद्रों से बाहर निकाल दिया।

सीएम सैनी असम में विधायक दल चयन के सह-प्रभारी नियुक्त

हरियाणा डेस्क । हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया के लिए सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया यह निर्णय आगामी राजनीतिक रणनीतियों और राज्य में नेतृत्व चयन को सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार, नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी उनके संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए सौंपी गई है।

तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने टीवीके को दिया समर्थन

चेन्नई। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार गठन के लिए पार्टी से समर्थन मांगा है और इस बारे में अंतिम निर्णय कांग्रेस की राज्य इकाई लेगी। इसके लिए तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुधवार को सुबह होगी। राज्य में टीवीके बहुमत से 10 सीटें दूर है जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस बारे में मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक की। बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तमिलनाडु राज्य इकाई के कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडंकर सहित कई लोग उपस्थित थे। बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, टीवीके अध्यक्ष थिरु विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस मानती है कि तमिलनाडु में मिला जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर भाजपा और उसके सहयोगियों को तमिलनाडु की सरकार में शामिल नहीं होने देना चाहती। हम तमिलनाडु सरकार में भाजपा और उसके सहयोगियों को किसी भी रूप में शामिल नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु में पार्टी की राज्य ईकाई को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है।

वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि विजय ने कामराज से प्रेरणा लेने की बात कही है। उन्होंने कहा, तदनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) को थिरु विजय के अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य की भावनाओं और चुनावी जनादेश को ध्यान में रखा जाएगा। विजय की टीवीके ने 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कुछ कम है। सरकार बनाने के लिए उन्हें कम से कम 10 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने पांच सीटें जीती हैं, जबकि पीएमके ने चार, सीपीआई और सीपीआई-एम ने दो-दो सीटें हासिल की हैं।

बंगाल में जश्न मनाने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे राहुल, कहा-

टीएमसी की हार पर खुश न हों कांग्रेसी

छोटी राजनीति से ऊपर उठें

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया है जो इस हार पर खुशी जता रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी की हार पर बगलें बजाने (खुश होने) की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा कांग्रेस में कुछ लोग और अन्य दल टीएमसी की हार पर जश्न मना रहे हैं। उन्हें यह साफ समझने की जरूरत है - असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के भाजपा के मिशन में एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने आगे अपील करते हुए कहा कि यह समय छोटी राजनीति करने का नहीं है, बल्कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने का है।

ममता बनर्जी के वोट चोरी के आरोपों का किया समर्थन

राहुल गांधी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से जनादेश चुराया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बंगाल में भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। उन्होंने असम के चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी कदम बताया।

ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को बताया अनैतिक

इससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को अनैतिक और अवैध करार दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं।

चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग बन गया है। हमने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह कोई नैतिक जीत नहीं है। पीएम, गृह मंत्री और केंद्रीय बलों ने मिलकर जो किया, वह पूरी तरह अवैध है।

बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट

जालंधर । जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। इसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। जिस एक्टिवा स्कूटी में विस्फोट हुआ, वह कथित तौर पर एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी कर्मी की बताई जा रही है। वह शाम करीब 8:15 बजे स्कूटी खड़ी कर बीएसएफ हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल देने गया था, इसी दौरान पीछे स्कूटी में विस्फोट हो गया। सूत्रों का कहना है स्कूटी रखे किसी विस्फोटक के फटने की आशंका है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के साथ गुरुनानकपुरा जाने वाली सड़क पर स्थित सब्जी मंडी में उस समय लोग खरीदारी कर रहे थे। अचानक तेज आवाज सुनकर लोग सहम गए और कुछ देर तक स्थिति को समझ नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा- स्कूटी में आग लगने के बाद ही विस्फोट हुआ है। अभी यही जानकारी मिली है। स्कूटी पर दो लड़के आए थे दोनों लड़कों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में रखा है। हिरासत में लिए गए एक लड़के के पिता ने बताया कि बेटा हर रोज बीएसएफ में पार्सल की डिलीवरी देने आता था। आज भी उसने शाम को पार्सल फ्लिपकार्ट स्टोर से उठाए थे। जब वह हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल छोड़कर बाहर आ रहा था, तभी स्कूटी विस्फोट के साथ उड़ गई। वह स्कूटी से 100 मी. दूर था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बीएसएफ हेडक्वार्टर की दीवारें तक हिल गईं।

स्कूटी में हुआ धमाका, कैंपस की दीवारें हिलीं पुलिस कमिश्नर बोलीं- 2 लोग हिरासत में लिए

अखिलेश बोले- 2027 चुनाव में महिला आरक्षण लागू करे सरकार, भाजपा ने प. बंगाल में मनमर्जी से परिणाम निकाला

लखनऊ ।

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले प्रावधान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तुरंत लागू करने की घोषणा की जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि या तो वह 2027 तक इसे लागू करने की स्पष्ट समयसीमा बताए या फिर खुले तौर पर स्वीकार करे कि वह महिलाओं के हितों के खिलाफ है। यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी पार्टी का 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठजोड़ महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार इस मुद्दे पर चुप रहती है, तो समाजवादी पार्टी इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदल देगी और हर समाह अलग-अलग स्थानों पर इसे उठाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें मोदी ने पहले समाजवादी पार्टी पर संसद में महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया था। यह मांग ऐसे समय आई है जब हाल ही में संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। लोकसभा में इसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। 298 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 230 ने विरोध किया, जबकि पारित होने के लिए 352 वोट जरूरी थे। विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव से पहले महिलाओं और पीडीए वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।

राष्ट्रपति भवन के दर पहुंची आप- राघव चड्ढा ने लगाए उत्पीड़न के आरोप, सीएम मान बोले-सात एमपी की मान्यता रद्द हो

चंडीगढ़ ।

आम आदमी पार्टी के बीच चल रही रार आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। वहीं उनसे पहले आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

राघव चड्ढा ने आप सरकार पर लगाया आरोप

मुलाकात के बाद सांसद राघव चड्ढा ने आप और पंजाब सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि पंजाब सरकार किस तरह उन सांसदों के खिलाफ बदले की खतरनाक राजनीति के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने आप छोड़कर भाजपा ज्वॉइन कर ली है। वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब पुलिस की मदद से गद्दार लिख दिया था। इसके बाद, पंजाब में पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता की फैक्टरी का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। आप ने संदीप पाठक के खिलाफ भी दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवाई, और मीडिया के जरिए यह बात फैलाई गई कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन्होंने विजिलेंस बोर्ड और प्रदूषण बोर्ड की मदद से बदले का एक खतरनाक खेल शुरू किया है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूत्रों के मुताबिक, अगला निशाना मैं हूं। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया पर हमें धमकाने के लिए एजेंसियों को हायर किया है। आप यह सब पंजाब सरकार के फंड का इस्तेमाल करके कर रही है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि आप भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसी हुई है।

सीएम मान बोले-पंजाब के साथ धोखा किया

वहीं मुलाकात के बाद सीएम मान ने कहा कि आज राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की है। असंविधानिक तरीके से पार्टियों को तोड़ना और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को भाजपा की वाशिंग मशीन में साफ करना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की घटिया चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाबी कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। आपका लोक सेवक होने के नाते मैं हर पंजाबी को विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता के जनादेश और संविधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट है।

इस प्रकरण पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, सुना है कि सीएम मान वोल्वो बसों में सभी विधायकों को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सीएम को बहुत ध्यान रखना होगा कहीं आप विधायकों की बस भाजपा कार्यालय की ओर न मुड़ जाए।

बंगाल में नई सरकार की शपथ 9 मई को- शाह पर्यवेक्षक होंगे

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अहम संगठनात्मक कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति राज्य में विधायक दल के नेता के चयन और सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी 5 मई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे.

ओडिशा के सीएम को बनाया सह-पर्यवेक्षक

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. दोनों नेता मिलकर राज्य में विधायक दल की बैठक और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे.

अहम होगा शाह का बंगाल दौरा

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह का बंगाल दौरा संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद पार्टी अब तेजी से सरकार गठन की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है.